

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद की प्रेस वार्ता का संपादित  
प्रतिलेख: 6 अगस्त, 2025 (बुधवार)

**भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:**

श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री स्वामिनाथन जे. - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. पूनम गुप्ता - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. राजीव रंजन - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. ए. आर. जोशी - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

**संचालक:**

श्री पुनीत पांचोली - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

**पुनीत पांचोली:**

नमस्ते। वित्त वर्ष 2025-2026 की तीसरी मौद्रिक नीति के बाद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं गवर्नर - श्री संजय मल्होत्रा; उप गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव; श्री टी. रबी शंकर; श्री स्वामिनाथन जे; और डॉ. पूनम गुप्ता का स्वागत करता हूँ। मैं कार्यपालक निदेशकों, डॉ. राजीव रंजन और डॉ. अजीत जोशी, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य सहयोगियों का भी स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले, मैं यहां उपस्थित मीडिया के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मोबाइल फोन बंद कर दें या साइलेंट रखें। इसके अलावा, कृपया प्रति व्यक्ति केवल एक प्रश्न तक सीमित रहें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि सभी को प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके। प्रश्न पूछते समय, कृपया अपने सामने लगे माइक्रोफोन को चालू करें, ताकि जो अन्य लोग इससे लॉग ऑन हैं या इसे स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, वे सुन सकें। और जब आप समाप्त कर लें, तो कृपया इसे बंद कर दें। और सर, आज मीडिया के 23 प्रतिभागी हैं, और आपकी अनुमति से, मैं नाम लेना शुरू करूंगा।

**संजय मल्होत्रा:**

जी, कृपया।

**पुनीत पांचोली:**

तो, मैं सुश्री लता से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा।

**लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी 18:**

अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, गवर्नर महोदय। आपने विकास का अनुमान 6.5% पर बनाए रखा है और अगली अवधि के लिए पूर्वानुमान 6.6% दिया है। आपने शुल्क के प्रभाव को कितना शामिल किया है? क्या शुल्क को लेकर स्पष्टता की कमी है और इसलिए कुछ भी शामिल नहीं किया गया है? और इसलिए, यदि शुल्क बने रहते हैं या यहां तक कि बढ़ते हैं, तो क्या इस संभावना है कि आप इसे कम करेंगे? मैं आपसे विशेष रूप से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पूरे भाषण में 'मौद्रिक सहजता के लिए बहुत ही सीमित गुंजाइश' वाक्यांश अनुपस्थित है। तो, यदि आप दरें कम करते हैं, तो क्या यह वाक्यांश फिर से आएगा या इस बात की कोई संभावना नहीं है कि यह वाक्यांश आएगा क्योंकि आने वाले वर्ष में मुद्रास्फीति 4.9% है?

**संजय मल्होत्रा:**

तो, सबसे पहले, विकास के संदर्भ में, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने पहले ही अपने अनुमान को, जो पहले 6.7% था, घटाकर 6.5% कर दिया है। इसलिए, कुछ वैश्विक अनिश्चितताओं को पहले ही संशोधित विकास अनुमान में शामिल कर लिया गया है। हालांकि, जैसा कि मेरे वक्तव्य में भी उल्लेख किया गया था, अभी भी बहुत अधिक अनिश्चितता बनी हुई है, और यह वास्तव में यह भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है कि प्रभाव क्या होगा। आगे चलकर, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, हम आने वाले आंकड़ों पर बहुत-बहुत बारीक नजर रखेंगे और निर्णय लेंगे। वर्तमान में, हमारे पास अपने सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों में संशोधन करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। 'बहुत ही सीमित गुंजाइश' शब्द या वाक्यांश की अनुपस्थिति पर आपके प्रश्न के संबंध में, वह संदर्भ तब था जब हम निभावकारी से उदासीन की ओर बढ़े थे, हम उदासीन ही बने हुए हैं। और इसलिए, आपको इस वक्तव्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता है।

**लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी 18:**

क्या यह इसलिए है क्योंकि (मुद्रास्फीति) 4.9% है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? यह वाक्यांश अनुपस्थित क्यों है? क्या यह उच्च मुद्रास्फीति के कारण है या इसलिए क्योंकि हमें विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है?

**संजय मल्होत्रा:**

देखिए, हम नीति-दर-नीति के आधार पर अपनी समष्टि आर्थिक स्थितियों की निगरानी जारी रखेंगे और तदनुसार निर्णय लेंगे। यह सब बहुत-बहुत अनिश्चित है। हम पहले ही

100 आधार अंककी दर कटौती कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मौद्रिक नीति का संचरण अभी भी चल रहा है। इसलिए, हम निश्चित रूप से मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए, अच्छे विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करते रहेंगे।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। दाहिनी ओर से, दूरदर्शन से, श्यामा जी प्रश्न पूछेंगी।

**श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:**

नमस्कार, सर। सर, क्या आरबीआई को इस बात की चिंता है कि ये वैश्विक बदलाव, व्यापार में बदलाव मुद्रास्फीति को बढ़ा देंगे क्योंकि आयात महंगा हो जाएगा?

**संजय मल्होत्रा:**

देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत में हम मुद्रास्फीति के मामले में बाहरी दुनिया पर कम निर्भर हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि कहीं कोई प्रभाव पड़ता भी है, तो वह विकास और मांग पर भी पड़ता है, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमने इसका उल्लेख किया है, हमने अपनी मौद्रिक नीति के वक्तव्य में, जो मैंने कुछ महीने पहले जारी किया था, इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की है कि यह दोनों दिशाओं में काम करता है। वर्तमान में, हमें इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है, जब तक कि हमारे पास प्रतिशोधी शुल्क आदि न हों, जिसकी मैं वास्तव में कल्पना नहीं करता। मैं महानिदेशक पूनम गुप्ता से अनुरोध करूंगा, क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगी?

**डॉ. पूनम गुप्ता:**

निश्चित रूप से। सर ने जो कहा, उसके अतिरिक्त, मुझे यह भी याद दिलाने दें कि हमारी मुद्रास्फीति की टोकरी का लगभग आधा हिस्सा खाद्य पदार्थों का है, जो वैश्विक घटनाक्रमों से सीधे प्रभावित नहीं होता है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा गैर-व्यापार योग्य वस्तुओं का है, जो फिर से वैश्विक घटनाक्रमों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए, उस हद तक, भारत की मुद्रास्फीति पर इन विकसित हो रही अनिश्चितताओं का प्रथम-क्रम (first order) प्रत्यक्ष प्रभाव बहुत ही सीमित होने की संभावना है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। धन्यवाद, मैडम। मैं मनीजीत साहा से बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए पूछूंगा।

### मनीजीत साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स:

धन्यवाद, सर। चूंकि आपने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को काफी कम करके 3.1% कर दिया है, तो एमपीसी को ब्याज दर में कटौती से क्या रोके हुए है? क्योंकि आपने संकेत दिया है कि आप भविष्यवादी होंगे और ब्याज दर के निर्णयों में अग्र-सक्रिय रहेंगे। तो, वास्तव में एमपीसी को दर कटौती से क्या रोक रहा है? और साथ ही, यदि आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें कि क्या मौद्रिक नीति ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने में प्रभावी है, क्योंकि 100 आधार अंक की दर कटौती के बावजूद ऋण वृद्धि धीमी बनी हुई है?

### संजय मल्होत्रा:

देखिए, नीतिगत दर को बनाए रखने के कारण हमारे संकल्प में बहुत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, जिसका उल्लेख मेरे वक्तव्य में भी आया था। मैं उन्हें दोहरा देता हूं। एक, हमने सबसे पहले अग्रिम-भारित (front-loaded) दर कटौती की, फरवरी से जून तक चार महीने की छोटी अवधि में 100 आधार अंक संचरण अभी भी चल रहा है। अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं। स्थिति अभी भी विकसित हो रही है। जहां तक मुद्रास्फीति का सवाल है, पूर्वानुमान कमोबेश वही हैं, यदि आप अत्यंत अस्थिर खाद्य पदार्थों को छोड़ दें। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहीं उल्लेख किया था कि लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) लागू होने के बाद से पिछले 8-9 वर्षों में हमारी समग्र और खाद्य मुद्रास्फीति 4.9% रही है। खाद्य मूल्यों में उतार-चढ़ाव औसतन 3% के क्षेत्र का है। विचलन, निरपेक्ष विचलन 3% है, 5.9 प्लस माइनस 3% औसत है। जबकि मुख्य में यह बहुत कम है, निरपेक्ष रूप से लगभग 1.1%। इसलिए, जो बदलाव हुए हैं, वे मुख्य रूप से खाद्य के कारण हैं, कोर मुद्रास्फीति के कारण नहीं। वास्तव में, कोर मुद्रास्फीति पिछले महीनों की तुलना में थोड़ी बढ़ी ही है। इसलिए, ये वे कारण हैं जिनके कारण हमने नीतिगत दर को बनाए रखा है। हम आने वाले आंकड़ों और अपनी समष्टि आर्थिक स्थितियों के विकसित हो रहे परिदृश्य पर नजर रखेंगे और एमपीसी बैठक-दर-बैठक नीति पर अपना दृष्टिकोण लेगा।

### संजय मल्होत्रा:

जहां तक दरों के प्रभाव का सवाल है, मैंने अपने वक्तव्य में आंकड़े दिए हैं। यह ऋण पक्ष पर लगभग 71 आधार अंक का है। जून तक चार महीने की अवधि में बैंक ऋण दरों में यह गिरावट आई है, जिसमें से कुल 71 आधार अंकों में से लगभग 55 आधार अंकदर में बदलाव के कारण हैं, न कि ऋण ऋणों के मिश्रण में बदलाव के कारण। तो, यह हुआ है। और जाहिर है, यह न केवल ऋण में वृद्धि में मदद करेगा, बल्कि इसका वास्तविक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार यह कुछ समय के अंतराल के साथ होता है, हालांकि दरें निश्चित रूप से काफी तेजी

से कम हुई हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इसका वृद्धि को बढ़ावा देने वाला प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**मनोजीत साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स:**

धन्यवाद।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया से श्री मयूर शेटी होंगे।

**मयूर शेटी, द टाइम्स ऑफ इंडिया:**

धन्यवाद, सर। आज सुबह आपने ऋण, ऋण मांग में धीमी गति के बारे में बताया, आपने कहा कि कुछ बदलाव अन्य वित्तीय साधनों की ओर हुआ है। लेकिन क्षेत्रीय आंकड़े दिखाते हैं कि आवास, जो आमतौर पर दरें कम होने पर बढ़ता है, धीमा हो गया है। आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है?

**संजय मल्होत्रा:**

मुझे लगता है कि सबसे पहले, डेटा को नियमित आधार पर, सूक्ष्म स्तर पर, महीने-दर-महीने, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें से संकेत निकालने के लिए, मुझे लगता है कि हमें उस डेटा से संकेत निकालने में संकोच करना चाहिए। इसलिए, किसी भी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक डेटा अधिक प्रासंगिक है। और दूसरी ओर, मैं यह भी इंगित करना चाहूंगा कि ये उतार-चढ़ाव होते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शोर होगा। इसलिए, हमें उस शोर को हटाना होगा। यदि आप वास्तव में महीने-दर-महीने, दिन-प्रतिदिन के आधार पर डेटा देख रहे हैं, तो उस शोर को हटाना बहुत कठिन हो जाता है।

यह कहे जाने के बाद, आवास ऋण, मुझे लगता है कि समग्र रूप से, यह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यह बहुत अच्छा कर रहा है। यह कुछ हद तक मध्यम हुआ हो सकता है, लेकिन ये अपेक्षित हैं। कुछ उतार-चढ़ाव होंगे। मुझे लगता है कि समग्र रूप से आवास ऋण 14% है जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है, जो हमारी इस वर्ष की औसत ऋण वृद्धि दर लगभग 10% से अधिक है। और जैसा कि मैंने उल्लेख किया, कुछ प्रभाव समय के अंतराल के साथ होता है, हमने दर कम की है। इसलिए, जबकि दरों में कमी आई है, इसका ऋण वृद्धि दर में अनुवाद होने में लोग समय लेते हैं... यह एक दीर्घकालिक निवेश है। आवास एक अल्पकालिक निवेश नहीं है। यदि आप बाजार

में जाते हैं, तो आप एक उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु खरीदते हैं, यह वैसा नहीं है। यह एक दीर्घकालिक निवेश है। इसलिए, इसका यहाँ भी प्रभाव पड़ता है।

### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद। अब, मैं जी बिजनेस से एकता सूरी जी से प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा।

### **एकता सूरी, जी बिजनेस:**

नमस्कार, सर। सबसे पहले तो बधाई हो, सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों में वित्तीय समावेशन के लिए शिविर लगाने के लिए आरबीआई का बहुत धन्यवाद किया है। सर, मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम इस बार के बैंकों के परिणामों को देखें, तो हमें एनपीए में वृद्धि दिखाई देती है, और यदि हम एमएफआई खंड की बात करें, तो आपने पिछली बार भी चिंता व्यक्त की थी कि इसमें एनपीए बढ़ रहे हैं। क्या हम इसके संबंध में नियमों और विनियमों को और सख्त होते हुए देख सकते हैं? विशेष रूप से तब जब एनबीएफसी प्राथमिकता क्षेत्र में धन जुटाते हैं लेकिन उनकी दरें साहूकारों की तरह बढ़ गई हैं। तो, क्या इसे कम करने के लिए नियमों को सख्त बनाए जाने की संभावना है?

और दूसरी बात, यदि हम 'म्यूलहंटर' की बात करें, तो कई बैंकों ने इसे लागू कर दिया है, तो आम लोगों को धोखाधड़ी के कारण खोया हुआ धन कितनी जल्दी वापस मिल सकता है? और अब उनका पैसा कितना सुरक्षित है? धन्यवाद, सर।

### **संजय मल्होत्रा:**

एकता, आपने एक साथ बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं। सबसे पहले, वित्तीय समावेशन पर हमें बधाई देने के लिए धन्यवाद। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमने इसे अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में भी उल्लेखित किया है। इसलिए, हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रयासों को अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाएं और इसका प्रचार करें ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आपने उल्लेख किया कि कुछ एनपीए बढ़े हैं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में भी उल्लेख किया है कि जब हम पूरे बैंकिंग क्षेत्र को देखते हैं, तो हमारे कुल सकल एनपीए 2.2% हैं और शुद्ध एनपीए 0.5% से 0.6% के बीच हैं, जो कि काफी संतोषजनक है, और इसमें वृद्धि नहीं हुई है। यह संभव है कि कुछ क्षेत्रों में, जैसा कि आपने एमएफआई और अरक्षित ऋणों में उल्लेख किया, कुछ एनपीए बढ़े हैं, जिसके कारण हमने ऋण जोखिम भार बढ़ाए हैं। हमने यह भी देखा था कि एमएफआई और असुरक्षित व्यक्तिगत ऋणों में ऋण दरों में वृद्धि हुई थी, जो बाद में कम हुई। तो, सामान्य तौर पर, हमारे लिए

चिंता की कोई बात नहीं है, और हम हमेशा प्रयासरत हैं। विशेष रूप से पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर, माइक्रोफाइनेंस के लोग 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये तक के ऋण ले रहे हैं, और यह हमारे सभी हितधारकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 8 करोड़ लोग हैं, एमएफआई के पास हालांकि राशि केवल 3,75,000 करोड़ रुपये, लगभग 4,00,000 करोड़ रुपये है, जबकि हमारे पास कुल ऋण 1,80,00,000 करोड़ रुपये है। यह उस राशि का केवल 2% है, लेकिन इसमें लगभग 8 करोड़ लोग शामिल हैं, क्योंकि हमारे कुल ऋण खाते 8 करोड़ हैं। लोगों की संख्या के मामले में यह कम हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी एक व्यक्ति दो तक ऋण लेता है। तो, यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उनके लिए हमें जो भी करना है, अधिक वित्तीय समावेशन के लिए, जैसे कि हम शिविर लगा रहे हैं, हम उस पर काम करते रहेंगे।

आपका तीसरा प्रश्न 'म्यूलहंटर' के बारे में है। सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष, हमने जिन वित्तीय धोखाधड़ियों को देखा, यदि आप कुल राशि को देखें, तो वह लगभग उतनी ही थी जितनी 2023-2024 में थी। इसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, यदि आप प्रति लेनदेन देखें, तो इसमें कमी आई है। तो, यह हमारे लिए संतोष की बात है। दूसरी बात, हमारा 'म्यूलहंटर' कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, अब 15 बैंक इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमें इस दिशा में निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।

**एकता सूरी, जी बिजनेस:**

धन्यवाद।

**पुनीत पंचोली:**

बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। अब, मैं एनडीटीवी प्रॉफिट से विश्वनाथ नायर जी से उनका प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा।

**विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:**

धन्यवाद, पुनीत सर। गवर्नर जी, अमेरिका से घोषित की गई शुल्क नीति उपायों के बाद जो तथाकथित अनिश्चितता की चर्चा है, वह अभी भी जारी है। वहां के राष्ट्रपति लगातार भारत पर विशिष्ट शुल्क को लेकर बयान दे रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने यह इशारा किया है कि ऐसे परिदृश्य में भारतीय व्यवसायों का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति उचित साधन नहीं हो सकती है। क्या ऐसी स्थिति में दरों में कटौती के अलावा और कुछ ऐसा है जो आरबीआई कर सकता है या करने के लिए तैयार है?

### **संजय मल्होत्रा:**

देखिए, हमने विकास का समर्थन करने के लिए कई उपाय किए हैं। यह केवल मौद्रिक नीति या चलनिधि पक्ष तक सीमित नहीं है; हमने विवेकपूर्ण विनियमन पक्ष पर भी उपाय किए हैं। यहां तक कि फेमा(विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के पक्ष में भी, मुझे लगता है कि अब एक मसौदा तैयार है, जिसे पेश किया जाएगा, ताकि व्यवसाय करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में आसानी हो। और हम ऐसे परिदृश्य में जो भी करना आवश्यक होगा, उसे करना जारी रखेंगे। निश्चित रूप से, व्यापार वार्ताएं अभी भी जारी हैं। हमें उम्मीद है कि हमें एक सुलह भरा समाधान मिलेगा।

### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास मनीकंट्रोल से हंसिनी हैं।

### **हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:**

हैलो गवर्नर सर, जब हम बैंकों से बात करते हैं, तो उनके सबसे बड़े भय में से एक विकास को लेकर है। वे यह भी देख रहे हैं कि उनकी जमाराशियों का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से जुड़े उत्पादों की ओर जा रहा है। बल्कि, जैसा कि बैंकर इसे कहते हैं, 'जमाराशियों का कॉर्पोरेटायजेशन' एक ऐसा रुझान है जिसे वे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस संदर्भ में, आप दरों के संचरण के लिए और कितनी गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि हमने उधारी के मामले में पहले ही स्वस्थ संचरण देखा है, आंकड़े 71 आधार अंक के आसपास हैं। उधारी पक्ष पर और जमा राशियों पर, यह 87 आधार अंक है। हमें फरवरी से 100 आधार अंक की कटौती मिली है। क्या आप बैंकों के लिए दरों में और कटौती की गुंजाइश देखते हैं, यह देखते हुए कि उनका तुलनपत्र भी अच्छा रहेगा? क्या उन्हें अधिक राशि का संचरण करना चाहिए? या फिर हमें दर कार्रवाई में लंबे विराम की उम्मीद करनी चाहिए? इन दोनों में से कौन सा अधिक संभावित है?

### **संजय मल्होत्रा:**

मुझे लगता है कि मैंने आपका उत्तर पहले ही दे दिया है। हम आने वाले आंकड़ों को देखते रहेंगे। और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) हर दो महीने में बैठक करती है, हम सभी संभावित परिदृश्यों पर विचार करेंगे। और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। मेरे लिए पूर्व-निर्णय करना उचित नहीं होगा। न केवल पूर्व-निर्णय, बल्कि वास्तव में, मेरे पास अभी कोई उत्तर नहीं है। हम देखेंगे। आज जो किया जाना था, वह कर दिया

गया है। तो, आइए हम दो महीने और प्रतीक्षा करें और देखें कि अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसे आकार लेती है, मौद्रिक नीति का संचरण वास्तव में कैसे हो रहा है, और वास्तविक अर्थव्यवस्था इन सभी चीजों का कैसे प्रतिक्रिया दे रही है। और फिर, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, हम फिर से उठाएंगे; हमें देश के विकास के लिए मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास का सही संतुलन प्रदान करने के लिए जो भी आवश्यक होगा, उसमें कमी नहीं पाई जाएगी।

**हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:**

धन्यवाद।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अब, मैं पीटीआई से श्री आशीष अगाशे से उनका प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा।

**आशीष अगाशे, पीटीआई:**

बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। सर, आपके आज के वक्तव्य और विशेष रूप से इस बात को रेखांकित करने के संदर्भ में कि खाद्य मुद्रास्फीति बहुत अस्थिर है और आपके अनुमान भी ऐसे हैं, क्या आप आगे की अवधि के लिए दरों के मोर्चे पर एक लंबे विराम की तैयारी कर रहे हैं?

**संजय मल्होत्रा:**

यह वही प्रश्न है जो एक अलग तरीके से पूछा गया है। इसलिए, मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ और नहीं है, क्षमा करें।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास ब्लूमबर्ग से श्री अनूप रॉय हैं।

**अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:**

सर, यदि भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करना पड़े या हमें रूस के साथ अपनी कुल तेल खरीद के उस 1% स्तर पर वापस लौटना पड़े जो पहले था, तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या आरबीआई ने इस पर कोई अध्ययन किया है या आपके पास कोई आकलन है?

**संजय मल्होत्रा:**

देखिए, मुद्रास्फीति कैसे आगे बढ़ती है, इसके बारे में कुछ बातें उप गवर्नर ने भी बताई हैं। निश्चित रूप से, कच्चा तेल हमारी मुद्रास्फीति निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन साथ ही, हमें दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह केवल रूसी तेल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हम केवल रूसी तेल ही नहीं ले रहे हैं। हम कई अन्य देशों से तेल ले रहे हैं। यदि यह समीकरण बदलता है, तो कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें क्या हैं? यह सब उसी पर निर्भर करेगा। और दूसरी बात यह है कि इसका प्रभाव नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क के रूप में कितना हिस्सा लिया जाता है। इसलिए, हमें अभी के तौर पर इससे मुद्रास्फीति पर कोई बड़ा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वहां कोई झटका लगता है, तो सरकार राजकोषीय पक्ष पर एक उचित निर्णय लेगी।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। ईटी नाउ स्वदेश से अनुराग शाह।

**अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:**

नमस्ते सर। सर, आपने आज तीन उपभोक्ता-केंद्रित नीतियों की घोषणा की हैं और उन तीन नीतियों के माध्यम से करोड़ों जन-धन खातों का पुनः केवाईसी किया जाएगा। उन्हें बीमा और पेंशन उत्पाद भी पेश किए जाएंगे। मैं यह समझना चाहता था कि 'म्यूल(ठगी) खाते' एक बड़ी समस्या बन गए हैं, जिसके बारे में आपने कहा है कि लेनदेन की संख्या में कमी आई है। लेकिन अब, यूपी पुलिस द्वारा एक और बड़ा मुद्दा उजागर किया गया है। यह पिछले महीने भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। इन खातों में कई बड़े बैंक भी शामिल हैं और कुछ लोगों की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन बड़े बैंकों के माध्यम से उनका केवाईसी किया जा रहा है। उनके खाते खोले जा रहे हैं। लेनदेन हो रहे हैं और यह बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो, उस दृष्टि से, यह पुनः केवाईसी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और सर, आपने उसी संदर्भ में कहा था कि बैंकों के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए 'आवश्यकता विश्लेषण' बहुत महत्वपूर्ण है। तो, सर, क्या आवश्यकता विश्लेषण के लिए कोई रूपरेखा होगी और आवश्यकता विश्लेषण कैसे किया जाएगा?

**संजय मल्होत्रा:**

आपने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और इसके लिए, रिजर्व बैंक और बैंक हमेशा सतर्क रहते हैं। चाहे आपने 'म्यूल (ठगी) खाते' की बात की हो, आपने

'पुनः केवाईसी' बात की हो, या आपने 'गलत बिक्री' की बात की हो। हमने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। हम 'म्यूल अकाउंट' के लिए पहले से ही एक परियोजना चला रहे हैं। हम जल्द ही इसे लागू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें इससे मदद मिलेगी। और गलत बिक्री के मामले में, हमने अपने बैंकों और विनियमित संस्थाओं को कई बार चेतावनी दी है। और निश्चित रूप से इसमें सुधार की गुंजाइश है। मैं यह नहीं कहूंगा कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें पहले से ही काफी सुधार हुआ है और हम इसमें और कदम उठाएंगे और इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।

#### **अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:**

सर, क्रेडिट-लिंक्ड इंश्योरेंस की बात है। यदि हम दुनिया भर में देखें, तो वहां नियामक हैं। कहीं भी क्रेडिट-लिंक्ड इंश्योरेंस नहीं है। केवल भारत में ही क्रेडिट-लिंक्ड इंश्योरेंस को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है।

#### **संजय मल्होत्रा:**

नहीं, मेरे अनुसार, ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत में है। आप शायद 'बैंकाश्योरेंस' की बात कर रहे हैं। आप शायद यह कह रहे हैं कि बैंक केवल भारत में ही बीमा उत्पाद बेचते हैं। यह सही नहीं है। कई अन्य देश भी हैं जहां बैंक बीमा उत्पाद बेच रहे हैं। अन्य उत्पाद भी बेचे जा रहे हैं। और इसका लाभ यह है कि हमारे पास पहले से ही एक नेटवर्क मौजूद है। यदि उसी नेटवर्क के माध्यम से एक से अधिक उत्पाद बेचे जाते हैं, तो लागत कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था के पैमाने में सुधार होता है। और वित्तीय समावेशन में भी मदद मिलती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो, उसी को ध्यान में रखते हुए, हमने यहां इसकी अनुमति दी है। और कई अन्य देश भी हैं जहां इसकी अनुमति है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि गलत बिक्री न हो। जैसा कि आपने कहा, 'आवश्यकता विश्लेषण' होना चाहिए। और उत्पादों को सही लोगों को बेचा जाना चाहिए। इसलिए, हमारा ध्यान इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने या बंद करने पर नहीं होना चाहिए।

#### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न द इकोनॉमिक टाइम्स से संगीता मेहता का होगा।

#### **संगीता मेहता, द इकोनॉमिक टाइम्स:**

धन्यवाद, सर। सर, आपने जमाराशियों के पक्ष में संचरणके बारे में बात की, लगभग 87 आधार अंक, और यह अभी भी जारी है। मैं आपसे यह समझना चाहती थीं कि यदि ब्याज दरें कम होती हैं, तो वित्तीय बचतों में जमाराशियों का हिस्सा गिरने की

संभावना है। तो, उस अर्थ में, यह धारणा भी है कि लोग जोखिम भरी संपत्तियों की ओर जाएंगे, बचतें म्युचुअल फंड जैसी उच्च-प्रतिफल वाली संपत्तियों में जाएंगी। तो, क्या आप इसे बैंकों की जमा वृद्धि और कॉरपोरेट्स को फंड देने की बैंकों की क्षमता को प्रभावित करते हुए देख रहे हैं?

**संजय मल्होत्रा:**

तो, मैं आपके दूसरे प्रश्न को पहले लेता हूँ। कॉरपोरेट्स को फंड देने की बैंकों की क्षमता, मुझे नहीं लगता कि इसके कारण यह किसी भी तरह से बाधित हो रही है। बैंकों के पास अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, चाहे वह कॉरपोरेट्स हों, घराने हों, या सरकारी क्षेत्र हो। तो, यह निश्चित रूप से बाधित नहीं है। हां, आपके पहले प्रश्न के संदर्भ में कि क्या कोई बदलाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से बैंकिंग से इक्विटी की ओर, ऋण से इक्विटी की ओर एक बदलाव है। मुझे लगता है कि समग्र रूप से, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ प्रवृत्ति है। जैसे-जैसे यह विकसित होती है, एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए और मुझे लगता है कि हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। हमें इसके बारे में अनुचित चिंता नहीं करनी चाहिए।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला, मैं इंफॉर्मिस्ट मीडिया से आर्यन को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करूंगा।

**आर्यन खन्ना, इंफॉर्मिस्ट मीडिया:**

सर, प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, केवल एक स्पष्टीकरण: क्या वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आपके अनुमानों में उस परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है जो सीपीआई बास्केट के भारांक में अगले वर्ष फरवरी में होने की उम्मीद है?

**संजय मल्होत्रा:**

नहीं।

**आर्यन खन्ना, इंफॉर्मिस्ट मीडिया:**

ठीक है, तो फिर प्रश्न पर आते हैं। मुद्रास्फीति के प्रक्षेपण से ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य मुद्रास्फीति का वर्तमान रुख लंबे समय तक नहीं चलेगा, अर्थात् आने वाली तिमाहियों में प्रमुख मुद्रास्फीति इसे हावी कर लेगी। क्या निरंतर अच्छी मानसून और

आपूर्ति पक्ष के उपाय अगले वर्ष भी सीपीआई को लगभग 4% के लक्ष्य के निकट नहीं रख सकते?

**संजय मल्होत्रा:**

देखिए, हमने अपने प्रक्षेपण दिए हैं, लेकिन जब हम यह प्रक्षेपण देते हैं, तो दोनों ओर जोखिम होते हैं। तो, क्या यह नीचे नहीं जा सकता? निश्चित रूप से, यह नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। यह आपके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है। ये प्रक्षेपण हैं, ये बहुत कठिन कार्य हैं। हमने पहले प्रक्षेपण किया था और न केवल हमने, बल्कि कुछ पेशेवर पूर्वानुमानों ने भी—जैसा कि आप जानते हैं—हम सभी ने 3.7% का प्रक्षेपण किया था। वास्तव में, उन्होंने इस वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति दर 3.8% का अनुमान लगाया था और इस बार हम सभी आश्चर्यचकित हुए हैं। इसलिए, ये प्रक्षेपण हैं, ये करना कठिन है। मैं निश्चित रूप से यह कहने की हिम्मत नहीं करूंगा कि यह इससे कम नहीं हो सकता।

**आर्यन खन्ना, इंफॉर्मिस्ट मीडिया:**

तो, बस इसी का अनुगमन करते हुए, क्या आप आगे चलकर प्रमुख सीपीई को अधिक प्राथमिकता देंगे, यह देखते हुए कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त में भी इसका उल्लेख किया गया था और आपने अपने वक्तव्य में भी इसका उल्लेख किया है?

**संजय मल्होत्रा:**

दोनों महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख और सुर्खियों वाली, दोनों ही मुद्रास्फीतियां महत्वपूर्ण हैं। किस समय किसको कितना भारांक दिया जाना है और आउटलुक क्या है, यह फिर से वह कुछ है जिसे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक-दर-बैठक देखती है। और मैंने कहा था तथा हमने रिकॉर्ड पर यह कहने के लिए कहा है कि खाद्य मूल्यों में अधिक अस्थिरता है, वे क्षणिक हो सकते हैं, इसलिए आपको इन चीजों को देखना होता है और कभी-कभी यदि आपको लगता है कि कुछ मुद्रास्फीति क्षणिक कारणों से है, तो उसे नजरअंदाज करना होता है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला, मेरे पास रॉयटर्स से स्वाति भट हैं।

**स्वाति भट, रॉयटर्स:**

धन्यवाद, सर। सर, बस व्यापार वार्ताओं पर ही बने रहते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सतह पर देखने से भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध कुछ हद तक खराब

भी हुए हैं। वहां क्या हो रहा है, इसके बारे में आप अधिक जानकार होंगे। लेकिन मैं केवल यह समझना चाहती थी कि क्या मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसका भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ेगा? और इसके बाद, रुपये पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप चिंतित हैं और आरबीआई के भीतर इस पर विचार कर रहे हैं? धन्यवाद।

#### **संजय मल्होत्रा:**

देखिए, विदेशी प्रवाह - चाहे वह आने वाले पूंजी प्रवाह हों या बाहर जाने वाले पूंजी प्रवाह - ये कई चीजों पर निर्भर करते हैं, दोनों चालू खाता और पूंजी खाता। वास्तव में, इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर काफी आत्मविश्वास है। हमारे पास वस्तु आयात के 11 महीनों के बराबर भंडार मौजूद हैं। इसलिए, हम बाह्य क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली किसी भी आवश्यकता को पूरा करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

#### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास ईटी नाउ से श्री अंकुर हैं।

#### **अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:**

धन्यवाद, पुनीत जी, अवसर देने के लिए। शुभ अपराहन, गवर्नर महोदय। आपने सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने अनुमानों को 6.5% पर ही बनाए रखा है। अपने वक्तव्य के बिंदु संख्या 10 में, आपने उल्लेख किया है कि विकास आपकी परियोजनाओं के अनुरूप मजबूत बना हुआ है, लेकिन आपकी 'आकांक्षाओं' से कम है। सबसे पहले, मैं यह जानना चाहूंगा कि वह आकांक्षित विकास दर क्या है जिसे आप देख रहे हैं? और दूसरी बात, पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी, तो आपने एक विशेष बैंक के नाम को लेकर आश्वासन दिया था। अब चूंकि वहां के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति हो गई है, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या बैंक की ओर से अभी भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई शेष है? क्योंकि सेबी के स्तर पर तो अंतिम आदेश अभी बाकी है, लेकिन क्या आरबीआई भी इस पर विचार कर रहा है? और क्या बैंक द्वारा दिए गए उत्तर या की गई कार्रवाई पर्याप्त है?

**संजय मल्होत्रा:**

देखिए, हम विशिष्ट संस्थाओं या बैंकों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए मैं उस प्रश्न से बचूंगा। लेकिन आपका पहला प्रश्न कि आकांक्षित विकास दर क्या है, तो वह निश्चित रूप से 6.5% से अधिक है। अतीत में, हमने औसतन 7.8% की विकास दर हासिल की है। हमने वह किया है। इसलिए, निश्चित रूप से हमें 6.5% से उच्च विकास दर की आकांक्षा करनी चाहिए।

**अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:**

धन्यवाद।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास द हिंदू से ललतेंदु मिश्रा हैं।

**ललतेंदु मिश्रा, द हिंदू:**

नमस्कार, गवर्नर महोदय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 'मृत' हो गई है। सर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

**संजय मल्होत्रा:**

नहीं, नहीं, मैं राष्ट्रपति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हां, मेरा मतलब है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विकास दर बहुत मजबूत है, 6.5%। वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, जब वे विश्व की 3% की विकास दर को देखते हैं, तो हम उसमें लगभग 18% का योगदान दे रहे हैं, जो कि अमेरिका से अधिक है, जहां योगदान की उम्मीद काफी कम, लगभग 11% या कुछ ऐसा है। इसलिए, हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम इसे और बेहतर बनाना जारी रखेंगे।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। यहीं दाहिनी ओर से, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से श्री महेश नायक।

**महेश नायक, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:**

शुभ अपराह्न, सर। अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या आज भारत पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए 'गोली खाने' - कठोर निर्णय लेने) के लिए तैयार है? मुझे इस पर आपका दृष्टिकोण जानना है, क्योंकि एक बहुत

मजबूत अर्थव्यवस्था होने के नाते, क्या आपको लगता है कि हम अस्थायी दर्द को सहन कर सकते हैं और पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता की ओर देख सकते हैं?

**संजय मल्होत्रा:**

वर्तमान में किसी भी परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अब द मिंट से श्रीमती गोपिका।

**गोपिका गोपाकुमार, द मिंट:**

नमस्कार, गवर्नर महोदय। यह प्रश्न पिछले एक महीने में हमने जो मुद्रा अवमूल्यन देखा है, उससे संबंधित है। डॉलर-रुपया विनिमय दर में लगभग 2.8% की वृद्धि हुई है। क्या यह दरों में कटौती करने की आरबीआई की क्षमता को सीमित कर रहा है? और दूसरा, अंकुर के प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, इसी प्रकार की परिस्थितियों में हमने देखा है कि आरबीआई ने बोर्ड को निलंबित किया है, अधिग्रहण किया है, और ऐसे बैंकों के बोर्ड में आरबीआई के नामित निदेशकों की नियुक्ति की है जहाँ धोखाधड़ी हुई है या धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। क्या आरबीआई इस विशेष मामले में प्रवर्तक या बोर्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, यह देखते हुए कि आरबीआई ने प्रवर्तक को हिस्सेदारी बढ़ाने और बोर्ड में दो नामित निदेशकों की नियुक्ति करने की भी अनुमति दी है?

**संजय मल्होत्रा:**

देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, हम विशिष्ट संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए मैं उस प्रश्न को छोड़ दूंगा। रुपए के अवमूल्यन के संदर्भ में, फिर से कहूंगा कि कुछ अस्थिरता रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत ही अनिश्चित समय में जी रहे हैं। इसलिए, कुछ अस्थिरता की उम्मीद की जाती है। यह अस्थिरता केवल हमारी मुद्रा में ही नहीं, बल्कि अमेरिका सहित अन्य देशों की मुद्राओं में भी देखी जा रही है। अमेरिकी मुद्रा में लगभग 10% की दोनों तरफ की गतिशीलता (मूल्यहास और मूल्यवृद्धि) देखी गई है। उस संदर्भ में, हमारी गतिशीलता बहुत कम है। इसका हमारी मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि मैंने कहा, यह कई चीजों का मिश्रण है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण घरेलू विकास और मुद्रास्फीति की गतिशीलता है।

## पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। इसी ओर से, द हिंदू बिजनेस लाइन से श्री पीयूष।

## पीयूष शुक्ला, द हिंदू बिजनेस लाइन:

शुभ अपराह्न, गवर्नर महोदय, महानिदेशक महोदय। धन्यवाद, पुनीत जी। सर, उच्च-स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अगले महीने तक सूचीबद्ध होना था। टाटा सन्स ने अपनी एनबीएफसी-सीआईसी के लाइसेंस के पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है। इस पर क्या अपडेट है? क्या आप उन्हें विस्तार देंगे या उनके अनुरोध को मंजूरी देंगे, यह पहला प्रश्न है। दूसरा, रवि शंकर सर, कुछ बैंकों ने वास्तव में भुगतान समेकक और कुछ श्रेणियों के व्यापारियों से यूपीआई पर शुल्क लेना शुरू कर दिया है। गवर्नर साहब ने अपने पिछले सार्वजनिक बयानों में उल्लेख किया था कि यूपीआई हमेशा के लिए मुफ्त नहीं रह सकता। तो, विनियामक दृष्टिकोण से, क्या आप बैंकों को इसकी अनुमति देते हैं? क्योंकि यह नहीं है, इसलिए वे किसी तरह इस विशेष चीज को मुद्रीकृत करना चाहते हैं। इस संबंध में आपके कोई विचार हैं? धन्यवाद।

## संजय मल्होत्रा:

पहले मैं बोल लेता हूँ, और फिर मैं मंच महानिदेशक रवि शंकर को सौंप दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम विशिष्ट संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों से बचते हैं। लेकिन, यह कहते हुए कि मैंने कहा था कि यह (यूपीआई) हमेशा के लिए मुफ्त नहीं रह सकता, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे खेद है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ; मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह हमेशा के लिए मुफ्त रह सकता है। प्रश्न, मुझे लगता है, इस आशय का था कि क्या आप देखते हैं कि उपभोक्ताओं पर एमडीआर आदि लगाया जाएगा। और मैंने वहां कहा था कि लागतें होती हैं। मैंने कहा था कि महत्वपूर्ण यह है कि लागतें होती हैं, और इन लागतों का भुगतान किसी को करना होता है। कौन भुगतान करता है, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बिल का भुगतान कोई तो कर रहा हो। इसलिए, हमारे लिए, वहनीयता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि चाहे सामूहिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से, इसके लिए कोई भुगतान करे। तो, मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह हमेशा के लिए मुफ्त नहीं रह सकता। मेरा मानना है कि यह अभी भी मुफ्त नहीं है। कोई न कोई इसके लिए भुगतान कर रहा है। सरकार इसे सब्सिडी दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं लागतों का भुगतान किया जा रहा है। वास्तविक प्रश्न यह है कि इसके लिए कौन भुगतान करता है। यह दूसरा प्रश्न है। लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि उपयोगकर्ताओं को भुगतान करना होगा। मैंने यह उल्लेख किया था कि सरकार की नीति ने वास्तव में यूपीआई के उपयोग के विस्तार में मदद की है और मैंने कुछ संख्याएं दी थीं - पिछले दो महीनों में यूपीआई लेनदेन 31 करोड़ प्रति

दिन से बढ़कर 61 करोड़ प्रति दिन हो गया है। तो, मैं इतना ही कहूंगा, और फिर मैं महानिदेशक रवि शंकर से अनुरोध करूंगा, यदि उन्हें कुछ जोड़ना हो।

**टी. रवि शंकर:**

कुछ और नहीं। मुझे लगता है कि इससे प्रश्न का उत्तर मिल गया है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, महोदय। अगले, मैं इंडियन एक्सप्रेस (Indian Express) से श्री हितेश से अनुरोध करूंगा।

**हितेश व्यास, इंडियन एक्सप्रेस:**

सर, मौद्रिक नीति रिपोर्ट में, आपने कच्चे तेल की कीमत 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और रुपया 86 (प्रति अमेरिकी डॉलर) मानकर कुछ धारणाएं बन गई हैं। क्या वर्तमान परिस्थिति में इसे बदलने की कोई आवश्यकता है?

**संजय मल्होत्रा:**

हमने अभी-अभी यह मॉडल तैयार किए हैं। हमने अभी यही धारणाएं ली हैं। वर्तमान में, स्पष्ट रूप से, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में क्या होता है, यह विकसित हो रहा है। चीजें बदलती रहती हैं। पहले, हमने कुछ अन्य संख्याएं ली थीं। और जैसे-जैसे डेटा आता है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये धारणाएं अपरिवर्तनीय हैं और मैं इन पर ही अडिग रहूंगा। नहीं। मैं इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा कि ऐसा कहूं। लेकिन वर्तमान में, हां, ये हमारे पास उपलब्ध सर्वोत्तम अनुमान हैं।

**पुनीत पंचोली:**

बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। अंत में, हमारे पास द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बेन होंगे।

**बेन कोचुवेदन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस:**

नमस्ते, सर। आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार खाद्य मूल्यों में अस्थिरता का उल्लेख किया है। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति से खाद्य बास्केट को हटाने को लेकर कुछ चर्चा या आह्वान किये जा रहे हैं। इस पर आरबीआई और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का क्या दृष्टिकोण है? क्या एमपीसी या आरबीआई के भीतर इस पर कोई चर्चा चल रही है?

**संजय मल्होत्रा:**

हमारा लक्ष्य निश्चित रूप से सुखियों की मुद्रास्फीति है। और लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे की समीक्षा का समय आ गया है। हम हर 5 साल में इसकी समीक्षा करते हैं। हम एक चर्चा पत्र तैयार कर रहे हैं, जिसे हम जनता की राय के लिए खोलेंगे। और उसके बाद, इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। हम इस बारे में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस पर अपने विचार सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

**लता वेंकटेश, सीएनबीसी - टीवी 18:**

क्या यह परामर्श निजी होगा या यह जनता के लिए भी होगा?

**संजय मल्होत्रा:**

हाँ। यह जनता के लिए भी होगा।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। इसके साथ, हम इस पत्रकार सम्मेलन को समाप्त करते हैं। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसे अत्यंत संवादात्मक बनाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपका दिन शुभ हो और अच्छा बीते।

**संजय मल्होत्रा:**

बहुत-बहुत धन्यवाद।